

उत्तराखंड का पर्वतीय प्रवास और जलवायु परिवर्तन: एक समाजिक एवं पर्यावरणीय अध्ययन

दिनेश कुमार¹, डॉ. अर्पणा जोशी²

शोधार्थी, विषय-समाजशास्त्र, महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली (उत्तर प्रदेश)¹

शोध निर्देशिका, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज, मुरादाबाद²

सारांश: देवभूमि उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा एक प्रमुख पर्वतीय राज्य है, जिसकी भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान अत्यंत विशिष्ट है। पिछले कुछ दशकों से यहां के पर्वतीय क्षेत्रों से होने वाला प्रवास एक गंभीर सामाजिक- आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौती के रूप में उभरा है। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन ने इस प्रवृत्ति को और अधिक बल दिया है।

पर्वतीय प्रवास के पीछे कई कारण हैं, सीमित कृषि योग्य भूमि, रोजगार के अवसरों की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव तथा प्राकृति आपदाओं की बढ़ती घटनाएं। जलवायु परिवर्तन में इन समस्याओं को और तीव्रता से हवा देने का काम किया है। तापमान में वृद्धि, वर्षा चक्र में असमानता, ग्लेशियरों का तेजी से पिघलने, भूस्खलन, बादल फटने जैसी घटनाओं ने पर्वतीय जीवन को असुरक्षित और अस्थिर बना दिया है। परिणाम स्वरूप युवा पीढ़ी रोजगार और बेहतर जीवन स्तर की तलाश में मैदानी क्षेत्र या महानगरों की ओर पलायन कर रही है, जिससे गांव में मुख्यतः बुजुर्ग और महिलाएं ही रह जाती हैं। यह शोध विभिन्न सरकारी रिपोर्ट जनगणना आंकड़ों और पूर्ववर्ती शोधों के आधार पर यह स्पष्ट करता है, कि जलवायु परिवर्तन न केवल कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है बल्कि जल स्रोतों के सूखने, मिट्टी के कटाव और पारंपरिक पशुपालन व्यवस्था के विघटन, अत्यधिक वर्षा और बादलों के फटने, पहाड़ों के खिसकने और आपदाओं का कारण भी बनता है। ये सभी कारण आजीविका संकट को जन्म देते हैं जो अंततः पलायन को बढ़ावा देते हैं। शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि पलायन और जलवायु परिवर्तन एक चक्रीय स्थिति को जन्म देते हैं। जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन ग्रामीण आजीविका को कमजोर करता है, पलायन बढ़ता है और जनसंख्या घटने से स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामुदायिक संरचना और भी कमजोर हो जाती है, इससे पारंपरिक ज्ञान संस्कृति धरोहर और सामाजिक एकजुटता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शोध पत्र इस और भी ध्यान आकर्षित करता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने

और प्रवास की गति को नियंत्रित करने के लिए बहुआयामी नीति हस्तक्षेप आवश्यक है। इसमें सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, जल संरक्षण, स्थानीय रोजगार सृजन, पर्यटन के पर्यावरण संवेदी मॉडल और आपदा प्रबंधन क्षमता की मजबूती आदि शामिल है। अतः शोध इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के सतत विकास के लिए जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन रणनीति को प्रवास नीति के साथ जोड़कर लागू करना होगा।

मुख्य शब्द: उत्तराखंड, पर्वतीय प्रवास, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा, आजीविका संकट।